

भारत कानून पुस्तकालय वेब संस्करण

इस उत्पाद का लाइसेंस है: राव धनबीर सिंह

डोसिड # IndLawLib/286095

(2001) सुप ए.सी.आर.सी. 912 : (1997) 1 ए.आई.सी.एल.आर. 417 : (1997) ए.आई.आर.(एस.सी.डब्लू.) 233 : (1997) ए.आई.आर.(एस.सी.) 610 : (1997) 21 ऑलसीआरएलरूलिंग्स 277 : (1997) 1 एंडएचएलडी(क्रिमिनल) 248 : (1997) 1 एपेक्सकोर्टजर्नल 158 : (1997) 2 बी.सी.आर. 666 : (1998) 1 बी.एल.जे.आर. 161 : (1998) कैलक्रिएलआर 45 : (1997) 1 सी.एल.आर. 204 : (1997) क्रिएलजे 743 : (1996) 4 अपराध 233 : (1997) 2 ई.सी.आर.सी. 391 : (1997) 2 जीएलआर 1631 : (1997) 1 जेटी 1 : (1998) 2 ओरिएलआर 556 : (1997) 13 उड़ीसाक्रिआर 214 : (1997) 1 आरसीआर (आपराधिक) 372 : (1997) 1 आरएलडब्ल्यू 94 : (1996) 9 स्केल 298 : (1997) 1 एससीसी 416 : (1997) एससीसी (क्रि) 92 : (1997) एससीसीआरआईआर 371 : (1996) एससीआर 284 : (1997) श्रीएलजे 236 : (1996) 8 सुप्रीम 581

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

डिवीजन बेंच

डीके बसु — अपीलकर्ता

बनाम पश्चिम बंगाल

राज्य — प्रतिवादी

(पहले: कुलदीप सिंह, जे; एस आनंद, जे)

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 539/1986.

निर्णय दिनांक : 18-12-1996

- भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 5
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) - धारा 167, धारा 174, धारा 176, धारा 41, धारा 46, धारा 49, धारा 50, धारा 53, धारा 54, धारा 56, धारा 57
- दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) - धारा 201, धारा 218, धारा 220, धारा 330, धारा 342

हिरासत में हिंसा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है (अनुच्छेद 21 और 22)। न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए हैं; अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य को मुआवज़ा देने के लिए सख्ती से उत्तरदायी होना चाहिए।

क. जनहित याचिका - उत्पत्ति और दायरा - हिरासत में हुई मौतों को रिट याचिका के रूप में मानने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र - पुलिस हिरासत में लगातार होने वाली हिंसा और मौतों से संबंधित मुद्दे का महत्व - सभी राज्यों और विधि आयोग से प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण - न्यायालय द्वारा एमिकस क्यूरी से सहायता मांगी जाना - हिरासत में हुई हिंसा को कानून के शासन और संरक्षकों की

जवाबदेही को प्रभावित करने वाली एक गंभीर चिंता के रूप में मान्यता - मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन के लिए उपाय के रूप में मौद्रिक मुआवजा। (पैरा 1, 2, 4, 6, 7, 9)

बी. मौलिक अधिकार - संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 - "जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता" में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और राज्य के अधिकारियों द्वारा यातना और हमले के खिलाफ गारंटी शामिल है - गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, जिसमें कारणों की जानकारी, वकील से परामर्श और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार शामिल है - ये अधिकार कानूनी प्रतिबंधों के अधीन विचाराधीन कैदियों, दोषियों, बंदियों और हिरासत में लिए गए अन्य कैदियों पर लागू होते हैं - हिरासत में हिंसा मानवीय गरिमा का खुला उल्लंघन और व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर एक सुनियोजित हमला है। (पैरा 9, 17, 22, 23)

सी. हिरासत में हिंसा और हिरासत में मृत्यु - संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद बढ़ती घटनाएं एक परेशान करने वाला कारक हैं - सबसे खराब मानवाधिकार उल्लंघन अक्सर थर्ड-डिग्री विधियों, यातना और स्क्रीनिंग गिरफ्तारी के माध्यम से जांच के दौरान होते हैं - पुलिस द्वारा रिकॉर्ड में हेरफेर और गवाह की अनिच्छा के कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई - पुलिस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा और पारदर्शिता की आवश्यकता। (पैरा 18, 24)

डी. गिरफ्तारी और नजरबंदी - गिरफ्तारी के लिए उचित संतुष्टि की आवश्यकता, केवल इसलिए नहीं कि यह वैध है - व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य सुरक्षा के बीच संतुलन का महत्व - जबकि राष्ट्र के हित में पूछताछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर वरीयता लेती है, जानकारी निकालने के लिए यातना या तीसरे दर्जे के तरीके अस्वीकार्य हैं और अनुच्छेद 21 के लिए अपमानजनक हैं - जांच के वैज्ञानिक तरीकों का विकास और जांचकर्ताओं का उचित प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है - राज्य आतंकवाद आतंकवाद से निपटने के लिए एक वैध प्रतिक्रिया नहीं है। (पैरा 20, 32, 33, 34)

ई. गिरफ्तारी और हिरासत के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय - कानूनी प्रावधान किए जाने तक निवारक उपायों के रूप में न्यायालय द्वारा जारी की गई आवश्यकताएं: पुलिस कर्मियों की स्पष्ट पहचान; गिरफ्तार व्यक्ति के गवाह और प्रति-हस्ताक्षर के साथ गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना; गिरफ्तारी और हिरासत स्थान के बारे में मित्र/रिश्तेदार को सूचना देना; कानूनी सहायता संगठन और अन्य जिलों के पुलिस स्टेशन को अधिसूचना; गिरफ्तार व्यक्ति को किसी को सूचित करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करना; गिरफ्तारी और दी गई सूचना के बारे में हिरासत डायरी में प्रविष्टि; गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच (चोटों को दर्ज करना) और हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में अनुमोदित चिकित्सक द्वारा जांच; इलाका मजिस्ट्रेट को दस्तावेजों की प्रतियां; पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने की अनुमति (पूरे समय नहीं); गिरफ्तारी की सूचना के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना। (पैरा 35, 36)

एफ. पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियाँ - गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित आवश्यकताएँ हिरासत और पूछताछ की शक्ति रखने वाले अन्य सरकारी अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होती हैं (जैसे, डीआरआई, ईडी, बीएसएफ, सीबीआई, आदि) - उनकी हिरासत में यातना और मृत्यु की घटनाओं के लिए समान सुरक्षा उपायों और प्रासंगिक कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होती है। (पैरा 31, 38)

जी. हिरासत में हिंसा के लिए उत्तरदायित्व और उपचार - अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य का दायित्व है - दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से हिरासत में लेने या स्वीकारोक्ति के लिए चोट पहुंचाने के लिए दंडित करने वाले वैधानिक प्रावधान (धारा 220, 330, 331 आईपीसी) अपर्याप्त हैं - अनुच्छेद 21 के स्थापित उल्लंघन के लिए आवश्यक पारंपरिक उपचारों के अतिरिक्त मौद्रिक मुआवजे का पुरस्कार - राज्य द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार के तहत मुआवजा, अपकृत्य के लिए दीवानी मुकदमे के नुकसान से अलग - मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य पर सख्त दायित्व का सिद्धांत लागू होता है; संप्रभु प्रतिरक्षा बचाव नहीं है - राज्य अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें गलत करने वाले से क्षतिपूर्ति का अधिकार है - मुआवजा प्रतिपूरक है, दंडात्मक नहीं, इसका उद्देश्य गलत को सुधारना है और आपराधिक दंड का विकल्प नहीं है - (पैरा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 55)

एच. "हिरासत न्यायशास्त्र" और जवाबदेही का विकास - हिरासत में मृत्यु के मुद्दों की जांच करने, न्यायशास्त्र विकसित करने और क्षतिपूर्ति तथा जवाबदेही के लिए तौर-तरीके तैयार करने की आवश्यकता - यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि अपराध दण्डित होने से न बचे और जवाबदेही तय हो - न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे सामाजिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करें और विधि के शासन तथा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वजनिक विधि क्षेत्राधिकार में नए उपकरण (जैसे प्रतिपूरक राहत) विकसित करें - न्यायालयों को संवेदनशील होना चाहिए और न्याय की विफलताओं को रोकने के लिए हिरासत में अपराध के मामलों में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए - विधि आयोग की 113वीं रिपोर्ट (हिरासत में चोट के मामलों में पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पूर्वधारणा) के सुझाव के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करने के लिए संसद से आह्वान। (पैरा 1, 8, 26, 27, 28, 45, 46, 52)

I. न्यायालय की अवमानना - गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने में अधिकारियों की विफलता को उल्लंघन माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई तथा न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का पात्र माना जाएगा। (पैरा 37)

अधिकारों के बारे में जागरूकता - हिरासत में अपराध से निपटने और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मीडिया (रेडियो, टीवी, पैम्फलेट) के माध्यम से गिरफ्तार लोगों के अधिकारों के बारे में जनता तक जानकारी का प्रसार करने का सुझाव दिया गया है। (पैरा 40)

उपस्थित पक्षों के वकील

अपीलकर्ता की ओर से वीआर रेड्डी, सॉलिसिटर जनरल, एनएम घटाटे, तापस रे, के. अमरेश्वरी और एएम सिंघवी;

संदर्भित मामले

- [मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी एवं अन्य](#), (1995) 4 जेटी 445 : (1995) 3 स्केल 343 : (1995) 4 एससीसी 262 : (1995) 1 एससीआर 44 सप्प
- [श्रीमती नीलाबती बेहरा उर्फ ललिता बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य](#), (1993) ACJ 787 : AIR 1993 SC 1960 : (1993) 76 CLT 98 : (1993) CriLJ 2899 : (1993) 2 JT 503 : (1993) 2 SCALE 309 : (1993) 2 SCC 746 : (1993) 2 SCR 581
- [रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य](#), एआईआर 1983 एससी 1086 : (1983) सीआरआईएलजे 1644 : (1983) 2 स्केल 103 : (1983) 4 एससीसी 141 : (1983) 3 एससीआर 508
- [कस्तूरीलाल रलिया राम जैन बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य](#), एआईआर 1965 एससी 1039 : (1966) 2 एलएलजे 583 : (1965) 1 एससीआर 375
- [भीम सिंह, विधायक बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य](#), (1986) एसीजे 867: एआईआर 1986 एससी 494: (1986) क्रिएलजे 192: (1985) 2 स्केल 1117: (1985) 4 एससीसी 677: (1986) 1 यूजे 458
- [राजेंद्र सिंह बनाम श्रीमती उषा रानी एवं अन्य](#), एआईआर 1984 एससी 956 : (1984) 1 स्केल 440 : (1984) 3 एससीसी 339 : (1984) 3 एससीआर 22 : (1984) 16 यूजे 313
- [जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य](#), एआईआर 1994 एससी 1349 : (1994) सीआरआईएलजे 1981 : (1994) 2 क्राइम 106 : (1994) 3 जेटी 423 : (1994) 2 स्केल 662 : (1994) 4 एससीसी 260 : (1994) 3 एससीआर 661
- [सहेली, एक महिला संसाधन केंद्र, सुश्री नलिनी भनोट और अन्य बनाम पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय और अन्य के माध्यम से](#), (1990) ACJ 345 : AIR 1990 SC 513 : (1990) 1 अपराध 469 : (1989) 4 JT 553 : (1990) 98 PLR 609 : (1989) 2 SCALE 1315 : (1990) 1 SCC 422 : (1989) 2 SCR 488 Supp : (1990) 1 UJ 434

आदेश

डॉ. आनंद, जे. - सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक गैर-राजनीतिक संगठन, कानूनी सहायता सेवा, पश्चिम बंगाल के कार्यकारी अध्यक्ष ने 26 अगस्त, 1986 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर उनका ध्यान 20, 21 और 22 जुलाई, 1986 के टेलीग्राफ और 17 अगस्त, 1986 के स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस में पुलिस लॉक-अप और हिरासत में मौतों के बारे में प्रकाशित कुछ समाचारों की ओर आकर्षित किया। कार्यकारी अध्यक्ष ने समाचारों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे की गहराई से जांच करना और "हिरासत न्यायशास्त्र" विकसित करना और पुलिस हिरासत में हुई अत्याचारों और मृत्यु के लिए पीड़ित और/या पीड़ित के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के लिए तौर-तरीके तैयार करना और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। पत्र में यह भी कहा गया था कि अक्सर लॉक-अप मौतों के मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और इस तरह अपराध दण्डित नहीं हो पाता और "फलता-फूलता रहता है"। अनुरोध किया गया कि पत्र तथा समाचार को "जनहित याचिका" श्रेणी के अंतर्गत रिट याचिका के रूप में माना जाए।

2. पत्र में उठाए गए मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए और हिरासत में हिंसा और पुलिस हवालात में मौतों के बारे में लगातार शिकायतों से चिंतित होकर, पत्र को रिट याचिका के रूप में माना गया और प्रतिवादियों को 9.2.1987 को नोटिस जारी किया गया।

3. नोटिस के जवाब में पश्चिम बंगाल राज्य ने जवाबी हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि पुलिस लॉक-अप में हुई मौत के किसी भी मामले को दबा नहीं रही है और जहां भी पुलिस कर्मियों को ऐसी मौत के लिए जिम्मेदार पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रतिवादियों ने रिट याचिका को गलत, भ्रामक और कानून के मुताबिक असमर्थनीय बताया।

4. जब रिट याचिका विचाराधीन थी, तब श्री अशोक कुमार जौहरी द्वारा 29.7.87 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें इस न्यायालय का ध्यान पुलिस हिरासत में अलीगढ़ के पिलखाना निवासी महेश बिहारी की मृत्यु की ओर आकर्षित किया गया था। उस पत्र को भी रिट याचिका के रूप में माना गया और श्री डी.के. बसु द्वारा दायर रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। 14.8.1987 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:

लगभग हर राज्य में आरोप हैं और इन आरोपों की आवृत्ति अब बढ़ती जा रही है, हिरासत में मौतों की, जिन्हें आम तौर पर अखबारों द्वारा लॉक-अप मौतों के रूप में वर्णित किया जाता है। वर्तमान में ऐसे आरोपों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं दिखता है। चूंकि यह सभी राज्यों से संबंधित एक अखिल भारतीय प्रश्न है, इसलिए सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करना वांछनीय है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वे इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए जाएं। भारत के विधि आयोग को भी इस अनुरोध के साथ नोटिस जारी किया जाए कि इस मामले में उपयुक्त सुझाव दिए जाएं। आज से दो महीने में नोटिस का जवाब दिया जाना चाहिए।

5. नोटिस के जवाब में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, मेघालय, महाराष्ट्र और मणिपुर राज्यों की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय विधि आयोग की ओर से भी हलफनामे दाखिल किए गए हैं।

6. रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, न्यायालय को बार से सहायता की आवश्यकता महसूस हुई और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी से न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया।

7. विभिन्न राज्यों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं और न्यायालय मित्र के रूप में डॉ. सिंघवी ने मामले को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया और यद्यपि राज्यों की ओर से शुरू में यह दिखाने का प्रयास किया गया कि उनके अपने राज्यों में "सब कुछ ठीक है", फिर भी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने, जैसा कि उनसे शामिल मुद्दे के महत्व को देखते हुए अपेक्षित था, अपने-अपने विवरण से ऊपर उठकर इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की जांच करने में इस न्यायालय को उपयोगी सहायता प्रदान की और हिरासत में हिंसा को रोकने के लिए, यदि नहीं तो उसे कम से कम करने के लिए, तथा हिरासत में हिंसा के पीड़ितों और यातना के कारण हिरासत में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कुछ सुझाव दिए।

8. भारतीय विधि आयोग ने भी इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में "पुलिस हिरासत में चोटें" के संबंध में 113वीं रिपोर्ट की एक प्रति भेजी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114-बी को शामिल करने का सुझाव दिया।

9. प्रत्येक मनुष्य के पुष्ट अधिकारों के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, नागरिकों के मौलिक और बुनियादी मानवाधिकारों के संरक्षक और रक्षक के रूप में, उनके उल्लंघन को रोकना न्यायालय का एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है। हिरासत में हिंसा, जिसमें लॉक अप में यातना और मृत्यु शामिल है, कानून के शासन पर

प्रहार करती है, जो मांग करती है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ न केवल कानून से प्राप्त होनी चाहिए, बल्कि कानून द्वारा उन्हें सीमित भी किया जाना चाहिए। हिरासत में हिंसा चिंता का विषय है। यह इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि यह उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्हें नागरिकों का रक्षक माना जाता है। यह पुलिस स्टेशन या लॉक-अप की चारदीवारी के भीतर वर्दी और अधिकार की आड़ में की जाती है, जहाँ पीड़ित पूरी तरह से असहाय होता है। पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा यातना और दुर्व्यवहार से किसी व्यक्ति की सुरक्षा एक स्वतंत्र समाज में गहरी चिंता का विषय है। ये याचिकाएँ पुलिस की शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के स्थापित उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। ये मुद्दे मौलिक हैं।

10. संविधान या अन्य दंड कानूनों में "यातना" को परिभाषित नहीं किया गया है। किसी इंसान द्वारा दूसरे इंसान को 'यातना' देना अनिवार्य रूप से 'कमज़ोर' पर 'मजबूत' की इच्छा को पीड़ा देकर थोपने का एक साधन है। आज यातना शब्द मानव सभ्यता के अंधेरे पक्ष का पर्याय बन गया है।

यातना आत्मा में एक ऐसा घाव है जो इतना दर्दनाक है कि कभी-कभी आप इसे छू भी सकते हैं, लेकिन यह इतना अमूर्त भी है कि इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। यातना आपके सीने में दबा हुआ दर्द है, बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर की तरह भारी, नींद की तरह लकवाग्रस्त और रसातल की तरह अंधेरा। यातना निराशा और भय और क्रोध और घृणा है। यह खुद को मारने और नष्ट करने की इच्छा है।

एड्रियाना पी. बार्टो

11. मानवाधिकारों में से किसी एक का उल्लंघन इतने सारे सम्मेलनों और घोषणाओं का विषय नहीं रहा है जितना कि 'यातना' - सभी का उद्देश्य सभी रूपों में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है, लेकिन यातना को खत्म करने के लिए किए गए वादों के बावजूद, तथ्य यह है कि यातना पहले से कहीं अधिक व्यापक है। "हिरासत में यातना" मानव गरिमा और अपमान का एक नग्न उल्लंघन है जो बहुत हद तक व्यक्तिगत व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। यह मानव गरिमा पर एक सुनियोजित हमला है और जब भी मानव गरिमा को चोट पहुंचाई जाती है, तो सभ्यता एक कदम पीछे हट जाती है - मानवता का झंडा ऐसे प्रत्येक अवसर पर आधा झुका होना चाहिए।

12. हिरासत में होने वाले सभी अपराधों में वास्तविक चिंता का विषय सिर्फ़ शारीरिक दर्द ही नहीं है, बल्कि मानसिक पीड़ा भी है जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन या लॉक-अप की चारदीवारी के भीतर झेलता है। चाहे वह शारीरिक हमला हो या पुलिस हिरासत में बलात्कार, व्यक्ति को होने वाले आघात की सीमा कानून के दायरे से बाहर है।

13. "हिरासत में हिंसा" और पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग न केवल इस देश की खासियत है, बल्कि यह व्यापक है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय रहा है क्योंकि यह समस्या सार्वभौमिक है और चुनौती लगभग वैश्विक है। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसने कुछ बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा और गारंटी के लिए दुनिया भर में चलन के उद्भव को चिह्नित किया, अनुच्छेद 5 में यह निर्धारित करता है कि "किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा।" पवित्र घोषणा के बावजूद, अपराध बेरोकटोक जारी है, हालांकि हर सभ्य राष्ट्र अपनी चिंता दिखाता है और इसके उन्मूलन के लिए कदम उठाता है।

14. इंग्लैंड में, अपराध, उसके साथियों और मामले की संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने या कबूलनामा प्राप्त करने के लिए यातना को एक सामान्य अभ्यास माना

जाता था, लेकिन आम कानून के विकास और मानवीय सोच और दृष्टिकोण को आत्मसात करने वाले अधिक कट्टरपंथी विचारों के साथ, इस तरह की अमानवीय प्रथाओं को शुरू में हतोत्साहित किया गया और अंततः लगभग समाप्त कर दिया गया, यहाँ-वहाँ कुछ विचलन के बावजूद। इंग्लैंड में गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ की पुलिस शक्तियों की सर सिरिल फिलिप्स समिति-क्रिमिनल प्रोसीजर पर एक रॉयल कमीशन की रिपोर्ट (कमांड-पेपर्स 8092 ऑफ 1981) द्वारा गहराई से जांच की गई थी। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट शिक्षाप्रद है। गिरफ्तारी की शक्ति के संबंध में, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति गिरफ्तारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित और सीमित होनी चाहिए, अर्थात्, संदिग्ध को साक्ष्य नष्ट करने या गवाहों के काम में हस्तक्षेप करने से रोकना या उन सहयोगियों को चेतावनी देना जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है या जहां अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका करने का उचित कारण है, तथा हर मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे उद्देश्य कुछ भी हो।

15. रॉयल कमीशन ने 'आवश्यकता सिद्धांत' के आधार पर गिरफ्तारी की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। रॉयल कमीशन ने कहा:

...हम अनुशंसा करते हैं कि किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी के बाद हिरासत केवल निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक के आधार पर जारी रहनी चाहिए:

- (क) व्यक्ति द्वारा स्वयं की पहचान बताने में अनिच्छा, ताकि उसे सम्मन भेजा जा सके;
- (ख) उस अपराध की निरंतरता या पुनरावृत्ति को रोकने की आवश्यकता;
- (ग) गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं या अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता;
- (घ) उस अपराध से संबंधित साक्ष्य को सुरक्षित या संरक्षित करने की आवश्यकता या संदिग्ध से पूछताछ करके उससे साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता; तथा
- (ई) किसी व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप का उत्तर देने के लिए न्यायालय में उपस्थित न होने की संभावना।

रॉयल कमीशन ने यह भी सुझाव दिया:

गिरफ्तारी के उपयोग को कम करने में मदद करने के लिए हम यहाँ एक ऐसी योजना की शुरूआत का भी प्रस्ताव करेंगे जिसका उपयोग ऑंटारियो में किया जाता है, जो पुलिस अधिकारी को उपस्थिति नोटिस जारी करने में सक्षम बनाता है। उस प्रक्रिया का उपयोग गिरफ्तारी का सहारा लिए बिना पुलिस स्टेशन में उपस्थिति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते गिरफ्तारी करने की शक्ति मौजूद हो, उदाहरण के लिए उंगलियों के निशान लेना या पहचान परेड में भाग लेना। इसे संदिग्ध और मामले की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के लिए सुविधाजनक समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थिति तक भी बढ़ाया जा सकता है...

16. रॉयल कमीशन द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर तथा पुलिस और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम, 1984 में शामिल किए जाने के बाद अब इंग्लैंड में गिरफ्तारी, पूछताछ और हिरासत की शक्ति को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और हिरासत में हिंसा की घटनाओं को बहुत हद तक कम कर दिया गया है।

17. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि "किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा"। इस प्रकार, संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक पवित्र और पोषित अधिकार है। "जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की अभिव्यक्ति में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है और

इस प्रकार इसमें राज्य या उसके पदाधिकारियों द्वारा यातना और हमले के खिलाफ गारंटी भी शामिल है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है और घोषित करता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और उसे अपनी पसंद के किसी कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और अपना बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 का खंड (2) निर्देश देता है कि गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कुछ संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं जो किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा किसी अनुचित हमले के विरुद्ध उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए हैं। संवैधानिक गारंटी के अनुरूप कई वैधानिक प्रावधान नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने का भी प्रयास करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय V किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्तियों और गिरफ्तार व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित है। Cr.PC की धारा 41 किसी भी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के किसी आदेश या गिरफ्तारी वारंट के बिना उसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 46 गिरफ्तारी की विधि और तरीके प्रदान करती है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कोई औपचारिकता आवश्यक नहीं है। धारा 49 के तहत, पुलिस को व्यक्ति के भागने को रोकने के लिए आवश्यक से अधिक संयम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। धारा 50 प्रत्येक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे उस अपराध का पूरा विवरण बताने का निर्देश देती है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है और ऐसी गिरफ्तारी के लिए आधार क्या हैं। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताने का भी निर्देश दिया गया है कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है और वह गैर-जमानती अपराध के लिए अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानतदारों की व्यवस्था कर सकता है। धारा 56 में एक अनिवार्य प्रावधान है जिसके तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाले इस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और धारा 57 भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (2) को प्रतिध्वनित करती है। धारा 53, 54 और 167 जैसे कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिनका उद्देश्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करना है। जब भी किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है, तो धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को मृत्यु के कारण की जांच करने की आवश्यकता होती है।

18. हालांकि, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के बावजूद, पुलिस हिरासत में यातना और मौतों की बढ़ती घटनाएं एक परेशान करने वाला कारक रही हैं। अनुभव से पता चलता है कि मानवाधिकारों का सबसे बुरा उल्लंघन जांच के दौरान होता है, जब पुलिस सबूत या कबूलनामे को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अक्सर यातना सहित थर्ड डिग्री विधियों का सहारा लेती है और गिरफ्तारी को दर्ज न करके या स्वतंत्रता के हनन को केवल लंबी पूछताछ के रूप में वर्णित करके गिरफ्तारी को छिपाने की तकनीक अपनाती है। लगभग हर रोज सुबह के अखबारों में पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों की हिरासत में अमानवीय यातना, हमला, बलात्कार और मौत की खबरें पढ़ना वास्तव में निराशाजनक है। हिरासत में यातना और मौत की बढ़ती घटनाएं इतनी खतरनाक हो गई हैं कि यह कानून के शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की

विश्वासनीयता को प्रभावित कर रही हैं। समुदाय उचित रूप से परेशान महसूस करता है। न्याय के लिए समाज की पुकार तेज होती जा रही है।

19. भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट ने हिरासत में हिंसा और हवालात में मौतों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। इसने हिरासत में यातना के कारण पूरे समाज पर पड़ने वाले मनोबल को कम करने वाले प्रभाव की सराहना की। इसने कुछ बहुत उपयोगी सुझाव दिए। इसने सुझाव दिया:

...किसी संज्ञेय मामले की जांच के दौरान गिरफ्तारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक में उचित माना जा सकता है:

(i) मामला हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है, तथा आतंकित पीड़ितों में विश्वास पैदा करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना तथा उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है।

(ii) अभियुक्त के फरार होने और कानूनी प्रक्रियाओं से बचने की संभावना है।

(iii) अभियुक्त हिंसक व्यवहार करता है तथा जब तक उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा आगे भी अपराध किए जाने की संभावना है।

(iv) अभियुक्त आदतन अपराधी है और जब तक उसे हिरासत में नहीं रखा जाता, तब तक उसके द्वारा फिर से इसी तरह के अपराध किए जाने की संभावना है। विभागीय निर्देशों के माध्यम से यह आग्रह करना वांछनीय होगा कि गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी केस डायरी में गिरफ्तारी के कारणों को भी दर्ज करे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वह निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है....

पुलिस आयोग (सुप्रा) की सिफारिशें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मौलिक अधिकार के संवैधानिक सहवर्ती तत्वों को प्रतिबिंबित करती हैं। हालाँकि, इन सिफारिशों को अभी तक कोई वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

20. यह न्यायालय [जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य.](#), (जिसमें हम में से एक, अर्थात्, आनंद, जे. भी एक पक्ष थे) ने गिरफ्तारी की पुलिस शक्ति के दुरुपयोग की गतिशीलता पर विचार किया और राय दी:

कोई गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि पुलिस अधिकारी के लिए ऐसा करना वैध है। गिरफ्तारी की शक्ति का अस्तित्व एक बात है। इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल दूसरी बात है.... किसी शिकायत की वास्तविकता और सद्भावना के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि प्राप्त किए बिना और व्यक्ति की मिलीभगत और गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में उचित विश्वास के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक गंभीर मामला है।

21. जोइन्दर कुमार के मामले (सुप्रा) में एक वकील की गिरफ्तारी शामिल थी, जिसे 7.1.94 को जांच के तहत एक मामले के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उसके ठिकाने के बारे में कोई संतोषजनक विवरण न मिलने पर हिरासत में लिए गए वकील के परिवार के सदस्यों ने 11.1.94 को इस न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक याचिकाकर्ता को आगे बढ़ाया और नोटिस के अनुपालन में वकील को 14.1.94 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस का कथन था कि 7.1.94 और 14.1.94 के दौरान वकील हिरासत में बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कुछ मामलों का पता लगाने में पुलिस की सहायता कर रहा था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने इसके विपरीत दावा किया। यह न्यायालय पुलिस के कथन से संतुष्ट नहीं था। यह देखा गया कि यद्यपि उस दिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में राहत नहीं दी जा सकती थी, लेकिन यह प्रश्न कि क्या वकील को 5 दिनों तक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता थी और यदि वह हिरासत में नहीं था, तो इस न्यायालय को इसकी

जानकारी क्यों नहीं दी गई, महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक था। इसके अलावा अगर 5 दिन तक हिरासत में रखा गया था, तो उसे किस कारण से हिरासत में रखा गया था। इसलिए, न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद को विस्तृत जांच करने और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने गिरफ्तारी के दौरान और उसके बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। इसने कहा:

मानवाधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। साथ ही, अपराध दर भी बढ़ रही है। हाल ही में, इस न्यायालय को अंधाधुंध गिरफ्तारियों के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं। हम दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं?

....

इस दिशा में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी का कानून व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को संतुलित करने का एक तरीका है। एक तरफ़, और दूसरी तरफ़ व्यक्तिगत कर्तव्य, दायित्व और ज़िम्मेदारियाँ, एक व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों और सामूहिक रूप से व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को तौलना और संतुलित करना; बस यह तय करना कि क्या चाहिए और कहाँ वज़न डालना है और यह तय करने पर ज़ोर देना कि कौन पहले आता है- अपराधी या समाज, कानून का उल्लंघन करने वाला या पालन करने वाला।

इसके बाद इस न्यायालय ने गिरफ्तारी के मामलों में कुछ प्रक्रियागत "आवश्यकताएं" निर्धारित कीं।

22. कानून के शासन द्वारा संचालित सभ्य समाज में हिरासत में मौत शायद सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) में निहित अधिकारों की पूरी ईमानदारी और ईमानदारी से रक्षा की जानी चाहिए। हम इस समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते। किसी भी तरह की यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है, चाहे वह जांच, पूछताछ या अन्य किसी भी तरह से हो। अगर सरकार के अधिकारी कानून तोड़ने वाले बन जाते हैं, तो इससे कानून के प्रति अवमानना पैदा होगी और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा और हर व्यक्ति में खुद कानून बनने की प्रवृत्ति होगी, जिससे अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी सभ्य राष्ट्र ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या कोई नागरिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर अपने जीवन के मौलिक अधिकार को त्याग देता है? क्या किसी नागरिक के जीवन के अधिकार को उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सकती है? ये सवाल मानवाधिकार न्यायशास्त्र की रीढ़ की हड्डी को छूते हैं। इसका उत्तर निश्चित रूप से एक जोरदार 'नहीं' होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत इस बहुमूल्य अधिकार से दोषियों, विचाराधीन कैदियों, बंदियों और हिरासत में लिए गए अन्य कैदियों को वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उचित प्रतिबंध न लगाए जाएं।

23. [मेंश्रीमती नीलाबती बेहरा उर्फ ललिता बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य,](#) (जिसमें आनंद, जे. एक पक्ष थे) इस न्यायालय ने बताया कि कैदियों और बंदियों को अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है और केवल ऐसे प्रतिबंध ही हैं जो कानून द्वारा अनुमत हैं, जिन्हें गिरफ्तार व्यक्तियों और बंदियों के मौलिक अधिकारों के आनंद पर लगाया जा सकता है। यह देखा गया:

यह स्वयंसिद्ध है कि दोषियों, कैदियों या विचाराधीन कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है और केवल ऐसे प्रतिबंध, जिनकी अनुमति कानून द्वारा दी गई है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकार के आनंद पर

लगाए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि जब तक नागरिक उसकी हिरासत में है, तब तक कानून के अनुसार ही किसी नागरिक के जीवन के अपूरणीय अधिकारों का उल्लंघन न हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत बहुमूल्य अधिकार को दोषियों, विचाराधीन कैदियों या हिरासत में अन्य कैदियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। उसकी स्वतंत्रता उसके कारावास के तथ्य से ही सीमित चीजों की प्रकृति में है और इसलिए उसके लिए छोड़ी गई सीमित स्वतंत्रता में उसका हित काफी कीमती है। यदि पुलिस की हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से जीवन से वंचित किया जाता है, तो अपराधी जवाबदेह है और राज्य जिम्मेदार है।

24. हमारे संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जहां पुलिस ने किसी व्यक्ति को किसी अपराध की जांच के सिलसिले में बिना वारंट के गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी दर्ज किए बिना, और गिरफ्तार व्यक्ति को आगे की जांच या मामले की संपत्ति की बरामदगी या कबूलनामा आदि के लिए उससे जानकारी निकालने के लिए यातना दी गई है। गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर दी गई यातना और चोट के कारण कभी-कभी उसकी मौत भी हो जाती है। हिरासत में मौत को आम तौर पर लॉक-अप के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता है और पुलिस द्वारा शव को ठिकाने लगाने या यह मामला बनाने का हर संभव प्रयास किया जाता है कि हिरासत से रिहा होने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति की मौत हो गई। भाईचारे के कारण ऐसी यातना या मौत के खिलाफ किसी भी शिकायत पर आम तौर पर पुलिस अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। पीड़ित या उसके परिजनों के कहने पर आम तौर पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है और यहां तक कि उच्च पुलिस अधिकारी भी ऐसी शिकायतों पर आंखें मूंद लेते हैं। यहां तक कि जहां पीड़ित या उसके परिजनों द्वारा औपचारिक अभियोजन चलाया जाता है, वहां भी यातना या चोट पहुंचाने के आरोप को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि पुलिस लॉक-अप जहां आम तौर पर यातना या चोट पहुंचाई जाती है, वह आम लोगों की नजरों से दूर होता है और गवाह या तो पुलिसकर्मी होते हैं या सह-कैदी जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिशोध के डर से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने के लिए बेहद अनिच्छुक होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिस हिरासत में यातना, मौत या चोट के खिलाफ शिकायत की जाती है, तो थर्ड डिग्री विधियों का सहारा लेने के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल होता है क्योंकि वे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के प्रभारी होते हैं, जिसमें हेरफेर करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। नतीजतन, अपराधी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन का परिणाम आम तौर पर बरी होना होता है। [मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी एवं अन्य](#), हमारे द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों को स्पष्ट करने वाला एक उपयुक्त मामला है। उस मामले में, नाथू बंजारा को पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन, रामपुरा में प्रताड़ित किया गया था। उसे गंभीर चोटें आने के कारण पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमे में प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत बचाव यह था कि नाथू को 13.10.1986 को ही पूछताछ के बाद रात लगभग 10.30 बजे रोजनामचा में प्रविष्टि प्र. पी/22ए के अनुसार पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया था और 14.10.1981 को लगभग 7.00 बजे पुलिस स्टेशन रामपुरा में रमेश प्रतिवादी संख्या 6 के कहने पर मृत्यु रिपोर्ट प्र. पी/9 दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसने टैंक के किनारे एक पेड़ के पास "एक अज्ञात व्यक्ति" को सीने में दर्द के साथ पाया था और जैसे ही प्रतिवादी संख्या 6 उसके पास पहुंचा, उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई। थाने के प्रभारी, प्रतिवादी नंबर 1, एसआई त्रिवेदी द्वारा स्थापित आगे का मामला यह था कि पुलिस स्टेशन से अपने प्रस्थान के बारे में 7.00 बजे रोजनामचा प्रविष्टि करने के बाद वह (प्रतिवादी नंबर 1-श्यामसुंदर त्रिवेदी) और कांस्टेबल राजाराम प्रतिवादी उस स्थान

पर गए, जहां पर शव पड़ा हुआ बताया गया था, ताकि सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच की जा सके। उन्होंने रमेश चंद्र और गोवर्धन प्रतिवादियों को मौके पर बुलाया और उनकी उपस्थिति में शव का पंचनामा एक्स. पी/27 तैयार किया, जिसमें यह राय दर्ज की गई कि मृत्यु का कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं था।

25. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी प्रतिवादियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया, यह मानते हुए कि प्रतिवादियों को अपराध से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। मध्य प्रदेश राज्य ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील की और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों 2 से 7 को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1, श्यामसुंदर त्रिवेदी को धारा 218 201 और 342 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया। हालांकि, धारा 302/149 और 147 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए उनकी बरी करने के फैसले को बरकरार रखा गया। राज्य ने विशेष अनुमति से इस न्यायालय में अपील दायर की। इस न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने हर उचित संदेह से परे निम्नलिखित परिस्थितियों को स्थापित किया था और पीडब्ल्यू 1, 3, 4, 8 और 18 के प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ मिलकर वे परिस्थितियाँ केवल प्रतिवादियों के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप थीं और उनकी निर्दोषता के साथ असंगत थीं:

(क) मृतक को जीवित पुलिस थाने में लाया गया था तथा उसे अंतिम बार दिनांक 13.10.81 को जीवित देखा गया था;

(ख) मृतक का शव दिनांक 14.10.81 को लगभग 2 बजे अपराह्न अस्पताल ले जाने के लिए थाने से बाहर ले जाया गया;

(ग) कि एसआई त्रिवेदी प्रतिवादी सं. 1, राम नरेश शुक्ला, प्रतिवादी सं. 3, राजाराम, प्रतिवादी सं. 4 और गनीउद्दीन प्रतिवादी सं. 5 पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और सभी ने नाथू-बंजारा के शव को ठिकाने लगाने के लिए हाथ मिलाया था;

(घ) कि एसआई त्रिवेदी, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपराध और उस मामले में अपराधी को छुपाने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य बनाए और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में झूठे सुराग गढ़े;

(ई) एसआई त्रिवेदी प्रतिवादी ने अपने कुछ अधीनस्थों के साथ मिलीभगत करके, मृतक को 'लावरी' बताते हुए जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करने के कदम उठाए थे, हालांकि मृतक की पहचान, जब उन्होंने काफी लंबे समय तक पूछताछ की थी, तो उन्हें अच्छी तरह से पता थी।

और कहा कि:

उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अपराध में इन प्रतिवादियों की उपस्थिति और भागीदारी संदिग्ध है, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से मेल नहीं खाती तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियों का अवास्तविक और अति सरलीकरण है।

26. हम में से एक (अर्थात्, जस्टिस आनन्द) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

अगर हम सम्मानपूर्वक कहें तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने में पूरी तरह से संवेदनशीलता की कमी और 'लापरवाही नहीं' वाला रवैया दिखाया और इस तरह कुछ पुलिस स्टेशनों पर गैरकानूनी होने के बावजूद इस्तेमाल किए जा रहे बर्बर थर्ड डिग्री तरीकों को बढ़ावा दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा हर उचित संदेह से परे सबूतों की स्थापना पर अतिरंजित पालन और जोर, जमीनी हकीकत, तथ्य स्थितियों और किसी दिए गए मामले की विशिष्ट परिस्थितियों की अनदेखी करते हुए, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, अक्सर न्याय की विफलता का कारण बनता है और न्याय वितरण प्रणाली को संदिग्ध बनाता है। अंतिम विश्लेषण में

समाज पीड़ित होता है और अपराधी को बढ़ावा मिलता है। पुलिस हिरासत में यातनाएं, जो हाल ही में बढ़ रही हैं, अदालतों के इस तरह के अवास्तविक दृष्टिकोण से प्रोत्साहित होती हैं क्योंकि यह पुलिस के मन में यह विश्वास मजबूत करता है कि अगर कोई बूढ़ा कैदी लॉक-अप में मर जाता है, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष के पास उन्हें सीधे यातना में फंसाने के लिए शायद ही कोई सबूत उपलब्ध होगा। न्यायालयों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पुलिस हिरासत में मौत शायद सभ्य समाज में सबसे खराब प्रकार का अपराध है, जो कानून के शासन द्वारा शासित है और एक व्यवस्थित सभ्य समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

इसके बाद न्यायालय ने सुझाव दिया:

न्यायालयों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दृष्टिकोण और रवैये में परिवर्तन लाएं, विशेष रूप से हिरासत में अपराध के मामलों में, तथा उन्हें हिरासत में अपराध के मामलों से निपटने के दौरान अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए तथा संकीर्ण तकनीकी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि जहां तक संभव हो सके, उनकी शक्तियों के भीतर, दोषी बच न पाएं, ताकि अपराध के पीड़ित को यह संतुष्टि मिले कि अंततः कानून की जीत हुई है।

27. राज्य की अपील स्वीकार की गई तथा प्रतिवादी 1, 3, 4 तथा 5 को दोषमुक्त करने के फैसले को खारिज कर दिया गया। प्रतिवादियों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1/34 के तहत अपराध शामिल है तथा उन्हें विभिन्न अवधि के कारावास तथा 20,000 से 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि नाथू बंजारा के उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया। आगे निर्देश दिया गया:

यदि अभियुक्त प्रतिवादियों द्वारा जुर्माना जमा कर दिया जाता है, तो विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उसका भुगतान मृतक नाथू बंजारा के उत्तराधिकारियों को किया जाए, तथा न्यायालय ऐसी सभी सावधानियां बरतेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि धन गलत हाथों में न जाए तथा मृतक नाथू बंजारा के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए उपयोग किया जाए, तथा यदि व्यावहारिक पाया जाए तो वह राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में ऐसी शर्तों पर जमा कर सकता है, जैसा कि विचारण न्यायालय मृतक के उत्तराधिकारियों के परामर्श से उचित और उचित समझे।

28. यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब अपराध के लिए कोई सजा नहीं मिलती है, तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है और समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। अपराध का शिकार या उसके परिजन हताश हो जाते हैं और कानून के प्रति अवमानना विकसित होती है। इन पहलुओं पर विचार करते हुए विधि आयोग ने अपनी 113वीं रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114बी को शामिल करने की सिफारिश की थी। विधि आयोग ने अपनी 113वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के कथित अपराध के लिए पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने में, यदि इस बात का सबूत है कि चोट उस अवधि के दौरान लगी थी जब व्यक्ति पुलिस की हिरासत में था, तो न्यायालय यह मान सकता है कि चोट उस अवधि के दौरान उस व्यक्ति की हिरासत में रहने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा लगी थी। आयोग ने आगे सिफारिश की कि न्यायालय को, अनुमान के प्रश्न पर विचार करते समय, हिरासत की अवधि, पीड़ित द्वारा दिए गए बयान, चिकित्सा साक्ष्य और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य सहित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार, सबूत के बोझ में बदलाव की वकालत की गई। श्याम सुंदर त्रिवेदी के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने यह भी उम्मीद जताई थी कि सरकार और विधानमंडल विधि आयोग की सिफारिश पर गंभीरता से विचार करेंगे। दुर्भाग्य से, सुझाए गए संशोधन को अभी तक कानून में शामिल नहीं किया गया है। संशोधन की

आवश्यकता पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है - हिरासत में हिंसा, यातना और हिरासत में मृत्यु में तीव्र वृद्धि, संशोधन की तत्काल आवश्यकता को उचित ठहराती है और हम संसद का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं।

29. इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस का कानूनी कर्तव्य है और उसे किसी अपराधी को गिरफ्तार करने तथा अपराध की जांच के दौरान उससे पूछताछ करने का वैध अधिकार है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कानून अपराध को सुलझाने के उद्देश्य से पूछताछ और जांच के दौरान हिरासत में आरोपी को थर्ड डिग्री के तरीकों या यातना के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। साध्य साधन को उचित नहीं ठहरा सकता। अपराध की जांच और पूछताछ सही मायने में उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए ताकि जांच प्रभावी हो सके। किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करके और थर्ड डिग्री के तरीकों का इस्तेमाल करके पुलिस बंद दरवाजों के पीछे वह सब कर रही होगी जिसकी हमारी कानूनी व्यवस्था मना करती है। कोई भी समाज इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

30. हम पुलिस शक्ति के दुरुपयोग को कैसे रोकें? कार्रवाई की पारदर्शिता और जवाबदेही शायद दो संभावित सुरक्षा उपाय हैं जिन पर इस न्यायालय को जोर देना चाहिए। बुनियादी मानवीय मूल्यों के अनुरूप पुलिस बल की कार्य संस्कृति, प्रशिक्षण और अभिविन्यास को ठीक से विकसित करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस की प्रशिक्षण पद्धति को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। बल में बुनियादी मानवीय मूल्यों को समाहित करने और संवैधानिक लोकाचार के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। जांच को संभालने वाले पुलिस कर्मियों के रवैये और दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे पूछताछ के दौरान बुनियादी मानवीय मूल्यों का त्याग न करें और पूछताछ के संदिग्ध तरीकों का सहारा न लें। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, पूछताछ के दौरान किसी समय गिरफ्तार व्यक्ति के वकील की उपस्थिति पुलिस को पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री तरीकों का उपयोग करने से रोक सकती है।

31. पुलिस के अलावा, कई अन्य सरकारी प्राधिकरण भी हैं जैसे राजस्व खुफिया निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, तटीय रक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), राज्य सशस्त्र पुलिस, खुफिया एजेंसियां जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, राॅ, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), सीआईडी, यातायात पुलिस, घुड़सवार पुलिस और आईटीबीपी, जिनके पास आर्थिक अपराधों, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम आदि के तहत अपराधों की जांच के संबंध में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उससे पूछताछ करने की शक्ति है। इन अधिकारियों की हिरासत में यातना और मौत के मामले भी हैं। सविंदर सिंह ग़ोवर की मृत्यु के संबंध में: (जिसमें कुलदीप सिंह, जे.) एक पक्ष थे) इस न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ हिरासत के दौरान सविंदर सिंह ग़ोवर की मृत्यु का स्वतः संज्ञान लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा जांच करवाने के बाद, जिसमें जांच और अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला सामने आया, इस न्यायालय ने सीबीआई को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट में नामित सभी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और उनके खिलाफ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। भारत संघ/प्रवर्तन निदेशालय को अंतरिम चरण में मृतक की विधवा को 2 लाख रुपये की राशि अनुग्रह राशि के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया। ऐसे मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन भी एक वास्तविक आवश्यकता है।

32. एक और पहलू भी है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत में पुलिस को एक कठिन और नाजुक कार्य करना पड़ता है, विशेष रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक उथल-

पुथल, छात्र अशांति, आतंकवादी गतिविधियों और अन्य बातों के अलावा अंडरवर्ल्ड और सशस्त्र गिरोहों और अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए। उग्रवादी, आतंकवादी, ड्रग तस्कर, संगठित गिरोह बनाने वाले तस्कर जैसे कई कट्टर अपराधी समाज में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक उदारीकरण और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ, नरम पूछताछ द्वारा ऐसे कठोर अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों का पता लगाने में कठिनाई होगी। उन क्षेत्रों में यह महसूस किया जाता है कि यदि हम उनके मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों के संरक्षण पर बहुत अधिक जोर देते हैं, तो ऐसे अपराधी बिना किसी तत्व या अंश के अपराध को उजागर किए बिना ही छूट जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप अपराध को दंडित नहीं किया जाएगा और अंततः समाज को नुकसान होगा। चिंता वास्तविक है और समस्या वास्तविक है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह समाज की अपेक्षाओं को देखते हुए और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि पुलिस को अपराधियों से कुशलतापूर्वक और प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए और अपराध में शामिल लोगों को सजा दिलानी चाहिए। हालाँकि, इलाज बीमारी से भी बदतर नहीं हो सकता।

33. मिरांडा बनाम एरिजोना, 384 यू.एस. 436 में इस तरह के मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया शिक्षाप्रद है। न्यायालय ने कहा:

इन मामलों में बार-बार यह तर्क दिया जाता है कि पूछताछ के लिए समाज की ज़रूरत विशेषाधिकार से ज़्यादा है। यह तर्क इस न्यायालय के लिए नया नहीं है। उदाहरण के लिए, चैंबर्स बनाम फ्लोरिडा, 309 यूएस 227: 84 1 एड 716, 60 एस-सीटी 472 (1940) देखें। हमारी पिछली चर्चा का पूरा जोर यह दर्शाता है कि संविधान ने सरकार की शक्ति का सामना करने पर व्यक्ति के अधिकारों को निर्धारित किया है, जब उसने पाँचवें संशोधन में प्रावधान किया कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उस अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।

(जोर हमारा)

34. यह कहने से कोई लाभ नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की सुरक्षा के लिए त्याग देना चाहिए। विभिन्न विधियों के तहत निर्धारित विभिन्न स्थितियों में राज्य की सुरक्षा के हित में व्यक्तियों की निवारक हिरासत के अधिकार को न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा गया है। राष्ट्र के हित में बंदियों, अपराधियों या गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करने के अधिकार को व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लैटिन कहावत सलस पॉपुली एस्ट सुप्रेमा लेक्स (लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है) और सलस रिपब्लिकन एस्ट सुप्रेमा लेक्स (राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है) सह-अस्तित्व में हैं और न केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं बल्कि इस सिद्धांत के मूल में हैं कि किसी व्यक्ति के कल्याण को समुदाय के कल्याण के लिए त्याग देना चाहिए। हालाँकि, राज्य की कार्रवाई "सही, न्यायसंगत और निष्पक्ष" होनी चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निकालने के लिए किसी भी तरह की यातना का इस्तेमाल करना न तो 'सही, न ही न्यायसंगत और न ही निष्पक्ष' होगा और इसलिए यह अनुच्छेद 21 के लिए अपमानजनक होने के कारण अस्वीकार्य होगा। ऐसे अपराध-संदिग्ध से पूछताछ की जानी चाहिए - वास्तव में कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित निरंतर और वैज्ञानिक पूछताछ के अधीन। हालाँकि, उसे जानकारी प्राप्त करने, कबूलनामा निकालने या उसके साथियों, हथियारों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है या थर्ड डिग्री विधियों के अधीन नहीं किया जा सकता है या उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा अनुमत तरीके को छोड़कर उसके संवैधानिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है, हालाँकि चीजों की प्रकृति में एक साधारण अपराधी की तुलना में ऐसे व्यक्ति से पूछताछ के तरीके में गुणात्मक अंतर होगा। आतंकवाद की चुनौती का सामना नए

विचारों और दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। राज्य आतंकवाद आतंकवाद से निपटने का कोई जवाब नहीं है। राज्य आतंकवाद केवल 'आतंकवाद' को वैधता प्रदान करेगा। यह राज्य, समुदाय और सबसे बढ़कर कानून के शासन के लिए बुरा होगा। इसलिए, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद से निपटने के लिए उसके द्वारा तैनात विभिन्न एजेंसियां कानून के दायरे में काम करें और खुद कानून न बनें। आतंकवादी द्वारा निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के कारण उसे दण्डित किया जा सकता है, लेकिन कानून द्वारा अनुमत तरीके के अलावा उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, जांच के वैज्ञानिक तरीके विकसित करने और जांचकर्ताओं को चुनौती का सामना करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

35. हमने जिन वैधानिक और संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त हमारा मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत के सभी मामलों की समसामयिक रिकॉर्डिंग और अधिसूचना के लिए उपयुक्त तंत्र की संरचना करना उपयोगी और प्रभावी होगा। यह वांछनीय है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी गिरफ्तारी के समय कम से कम एक गवाह की उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करे जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहाँ से गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी की तारीख और समय ज्ञापन में दर्ज किया जाएगा जिस पर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए।

36. इसलिए, हम यह उचित समझते हैं कि गिरफ्तारी या हिरासत के सभी मामलों में निवारक उपायों के रूप में निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि उस संबंध में कानूनी प्रावधान नहीं किए जाते हैं:

(1) गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों के पास उनके पदनाम के साथ सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और नाम टैग होने चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले सभी पुलिसकर्मियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

(2) गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है या उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहाँ से गिरफ्तारी की गई है। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जाएगा और इसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख लिखी होगी।

(3) कोई व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है और उसे किसी पुलिस थाने या पूछताछ केन्द्र या अन्य हवालात में हिरासत में रखा गया है, वह अपने किसी मित्र या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को, जो उसके कल्याण में रुचि रखता हो, यथाशीघ्र यह सूचित करने का हकदार होगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अमुक स्थान पर निरुद्ध किया जा रहा है, जब तक कि गिरफ्तारी ज्ञापन का सत्यापन करने वाला साक्षी स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या रिश्तेदार न हो।

(4) गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत का स्थल पुलिस द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तार व्यक्ति का अगला मित्र या रिश्तेदार जिले या शहर के बाहर रहता है, जिले में कानूनी सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर टेलीग्राफिक रूप से।

(5) गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार से अवगत कराया जाना चाहिए कि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाए या हिरासत में लिया जाए, किसी को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में सूचित किया जाए।

(6) व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में निरूद्धि स्थल पर डायरी में प्रविष्टि की जानी चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी की सूचना देने वाले व्यक्ति के निकटतम मित्र का नाम तथा गिरफ्तार व्यक्ति जिन पुलिस अधिकारियों की हिरासत में है, उनके नाम और विवरण भी प्रकट किए जाएंगे।

(7) गिरफ्तार व्यक्ति की, जहाँ वह ऐसा अनुरोध करता है, गिरफ्तारी के समय उसकी जाँच भी की जानी चाहिए और उसके शरीर पर यदि कोई बड़ी या छोटी चोट है, तो उसे उस समय दर्ज किया जाना चाहिए। "निरीक्षण ज्ञापन" पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

(8) हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल के डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा मेडिकल जांच की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को सभी तहसीलों और जिलों के लिए भी ऐसी दंडात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

(9) उपरोक्त उल्लिखित गिरफ्तारी ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां इलाका मजिस्ट्रेट को उनके रिकार्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।

(10) गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।

(11) सभी जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के स्थान के बारे में जानकारी गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर संप्रेषित की जाएगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसे एक सुस्पष्ट सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

37. उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के अलावा उसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित भी किया जा सकता है तथा न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही देश के किसी भी उच्च न्यायालय में शुरू की जा सकती है, जिसके पास मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार हो।

38. ऊपर बताई गई आवश्यकताएं संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) से आती हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ये अन्य सरकारी एजेंसियों पर भी समान रूप से लागू होंगी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

39. ये अपेक्षाएं संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त हैं तथा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के संबंध में न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिए गए विभिन्न अन्य निर्देशों से अलग नहीं हैं।

40. ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं को प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को भेजा जाएगा और यह उनका दायित्व होगा कि वे इसे अपने प्रभार के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में प्रसारित करें और प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक प्रमुख स्थान पर इसे अधिसूचित करवाएं। दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाए जाने के अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर आवश्यकताओं को प्रसारित करना और आम जनता की जानकारी के लिए इन आवश्यकताओं वाले स्थानीय भाषा में पर्चे प्रकाशित और वितरित करना भी उपयोगी होगा और व्यापक हित में होगा। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना हमारी राय में हिरासत में

अपराध की बुराई से निपटने और पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में सही कदम होगा। यह आशा की जाती है कि ये आवश्यकताएं पूछताछ और जांच के दौरान संदिग्ध तरीकों के इस्तेमाल को रोकने में मदद करेंगी, अगर पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगी, तो हिरासत में अपराध करने की ओर ले जाती हैं।

दंडात्मक उपाय

यूबीआई जस इबी रेमेडियम- बिना उपाय के कोई गलत नहीं होता। कानून चाहता है कि हर मामले में जहां किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ हो और उसे कोई नुकसान न पहुंचा हो, उसके पास उपाय होना चाहिए। किसी कार्रवाई की अमान्यता की घोषणा या हिरासत में हिंसा या लॉक-अप में मौत का पता लगाना, अपने आप में उस व्यक्ति को कोई सार्थक उपाय प्रदान नहीं करता है जिसके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

41. भारतीय दंड संहिता में कुछ दंडात्मक प्रावधान हैं जो जीवन के अधिकार के उल्लंघन को दंडित करने का प्रयास करते हैं। धारा 220 में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को दंडित करने का प्रावधान है जो भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है या कारावास में रखता है। धारा 330 और 331 में उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं या गंभीर चोट पहुंचाते हैं या किसी व्यक्ति से अपराध के बारे में स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करने के लिए जबरन वसूली करते हैं। धारा 330 के दृष्टांत (ए) और (बी) के अनुसार पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने या चोरी की गई संपत्ति को जमा करने के स्थानों को इंगित करने के लिए उसे प्रताड़ित करने का दोषी है। इसलिए धारा 330 सीधे तौर पर पूछताछ और जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता के तहत यातना को दंडनीय बनाती है। हालांकि, ये वैधानिक प्रावधान नागरिकों के साथ किए गए गलत कामों की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हैं। प्रत्येक अपराध के मामले में अपराधी का अभियोजन राज्य का दायित्व है, लेकिन अपराध के पीड़ित को आर्थिक रूप से मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इसलिए, जहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, वहां न्यायालय केवल घोषणा करके नहीं रुक सकता। उसे आगे बढ़ना चाहिए और क्षतिपूर्ति राहत देनी चाहिए, नागरिक कार्रवाई की तरह हर्जाने के रूप में नहीं बल्कि नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा न करने के राज्य द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण किए गए गलत काम के लिए सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार के तहत मुआवजे के रूप में। किए गए गलत काम की भरपाई करना और कानूनी क्षति के लिए न्यायिक निवारण देना न्यायिक विवेक की मजबूरी है।

42. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि, 1966 (ICCPR) के अनुच्छेद 9(5) में प्रावधान है कि "कोई भी व्यक्ति जो अवैध गिरफ्तारी या हिरासत का शिकार हुआ है, उसे मुआवजा पाने का प्रवर्तनीय अधिकार होगा"। बेशक, भारत सरकार ने 1979 में इसके अनुसमर्थन (ICCPR के) के समय इस आशय का एक विशिष्ट आरक्षण किया था कि भारतीय कानूनी प्रणाली अवैध गिरफ्तारी या हिरासत के पीड़ितों के लिए मुआवजे के अधिकार को मान्यता नहीं देती है और इस प्रकार वह संधि का पक्षकार नहीं बनता है। हालांकि, नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने वाले कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर अब वह आरक्षण अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। लाभ के साथ देखें [रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य](#), [राजेंद्र सिंह बनाम श्रीमती उषा रानी एवं अन्य](#), [भीम सिंह, विधायक बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य](#), [औरसहेली, एक महिला संसाधन केंद्र, सुश्री नलिनी भनोट और अन्य बनाम पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय और अन्य के माध्यम से](#), वास्तव में, जीवन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने के लिए भारत के संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी, इस

न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन के स्थापित असंवैधानिक वंचन के मामलों में मुआवजे के अधिकार को न्यायिक रूप से विकसित किया है।

43. लगभग दो दशक पहले तक सरकार की अपने लोक सेवकों के अपकृत्य कार्य के लिए देयता आम तौर पर सीमित थी और प्रभावित व्यक्ति सिविल मुकदमा दायर करके अपकृत्य में अपने अधिकार को लागू कर सकता था और फिर से संप्रभु प्रतिरक्षा के बचाव को अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, जीवन के मौलिक अधिकार या बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए, इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि लोक सेवकों के अपकृत्य कार्यों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के स्थापित उल्लंघन के लिए राज्य के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं है। नीलाबती बेहरा बनाम राज्य, (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय [कस्तूरीलाल रलिया राम जैन बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य](#), जिसमें राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व के मामले में संप्रभु प्रतिरक्षा की दलील को बरकरार रखा गया था, को इस प्रकार समझाया गया था:

इस संदर्भ में, यह कहना पर्याप्त है कि कस्तूरीलाल में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें राज्य के अपने सेवकों के अपकृत्यों के लिए संप्रभु उन्मुक्ति की दलील को बरकरार रखा गया है, अपकृत्य में उत्तरदायित्व के क्षेत्र तक सीमित है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य के उत्तरदायित्व से अलग है, जिसके लिए संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत का संवैधानिक योजना में कोई अनुप्रयोग नहीं है, और यह संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक उपाय का बचाव नहीं है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़ा देने में सक्षम बनाता है, जब मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का एकमात्र व्यावहारिक तरीका मुआवज़ा देना हो सकता है। रुदुल साह और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक उपाय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़ा देने से संबंधित हैं। दूसरी ओर, कस्तूरीलाल सरकारी सेवकों की गलती के कारण जब्त किए गए और मालिक को वापस नहीं किए गए माल के मूल्य से संबंधित है, दावा सामान्य प्रक्रिया के तहत रूपांतरण के अपकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का है, न कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़े का दावा। इसलिए, कस्तूरीलाल इस संदर्भ में अनुपयुक्त और विभेदनीय है।

44. संविधान के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के असंवैधानिक वंचन के लिए मुआवजे के लिए सार्वजनिक कानून में दावा, जिसकी सुरक्षा की गारंटी दी गई है, सख्त दायित्व पर आधारित दावा है और यह लोक सेवकों के अपकृत्य कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए निजी कानून में उपलब्ध दावे के अतिरिक्त है। सार्वजनिक कानून की कार्यवाही निजी कानून की कार्यवाही से अलग उद्देश्य पूरा करती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपूरणीय अधिकारों के स्थापित उल्लंघन के लिए मुआवजे का पुरस्कार सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है क्योंकि सार्वजनिक कानून का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक शक्ति को सभ्य बनाना है बल्कि नागरिकों को यह आश्वासन देना भी है कि वे एक कानूनी प्रणाली के तहत रहते हैं जिसमें उनके अधिकारों और हितों की रक्षा और संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के स्थापित उल्लंघन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 226 के तहत कार्यवाही में मुआवजे का अनुदान, गलत करने वाले को दंडित करने और राज्य पर सार्वजनिक गलत के लिए देयता तय करने के लिए सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार के तहत न्यायालयों का एक प्रयोग है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा है।

45. पीड़ित को केवल सिविल कानून में उपलब्ध उपायों के तहत ही सीमित रखने का पुराना सिद्धांत न्यायालयों की भूमिका को बहुत सीमित कर देता है, क्योंकि वे नागरिकों

के अपूरणीय अधिकारों के रक्षक और संरक्षक हैं। न्यायालयों का दायित्व नागरिकों की सामाजिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करना है, क्योंकि न्यायालय और कानून लोगों के लिए हैं और उनसे उनकी आकांक्षाओं पर प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय अपनी चेतना और जीवंतता को कठोर वास्तविकताओं से दूर नहीं रख सकता। अपराधी को केवल दण्डित करने से पीड़ित के परिवार को बहुत अधिक सात्वना नहीं मिल सकती- क्षतिपूर्ति के लिए सिविल कार्रवाई एक लंबी और बोझिल न्यायिक प्रक्रिया है। नागरिक के अपूरणीय जीवन के अधिकार के उल्लंघन का पता लगाने वाले न्यायालय द्वारा निवारण के लिए मौद्रिक मुआवजा, इसलिए, मृतक पीड़ित के परिवार के सदस्यों के घावों पर मरहम लगाने के लिए एक उपयोगी और कई बार शायद एकमात्र प्रभावी उपाय है, जो परिवार का कमाने वाला हो सकता है।

46. नीलाबती बहेरा के मामले (सुप्रा) में, यह आयोजित किया गया था:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के उल्लंघन या आक्रमण के लिए हिरासत में मृत्यु के शिकार व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को राहत प्रदान करने के संबंध में, राज्य के अपकृत्य कार्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए उसे सिविल मुकदमे के सामान्य उपाय पर छोड़ देना हमेशा पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि निजी कानून में वह उपाय वास्तव में पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपरिवर्तनीय अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने वाले नागरिक को यह नहीं बताया जा सकता है कि जीवन के मौलिक अधिकार के स्थापित उल्लंघन के लिए, उसे रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक कानून के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती है। सार्वजनिक कानून की कार्यवाही का प्राथमिक स्रोत विशेषाधिकार रिट से निकलता है और इसलिए, न्यायालयों को कानून के शासन को संरक्षित और सुरक्षित रखने की दृष्टि से स्थिति के अनुसार इसे ढालकर सार्वजनिक कानून में राहत देने के लिए नए उपकरण विकसित करने होंगे। 1949 में "कानून के तहत स्वतंत्रता" शीर्षक के तहत अपने पहले हैमलिन व्याख्यान का समापन करते हुए लॉर्ड डेनिंग ने अपनी शैली में चेतावनी दी:

कोई भी यह नहीं मान सकता कि कार्यपालिका कभी भी उन पापों के लिए दोषी नहीं होगी जो हम सभी के लिए समान हैं। आप निश्चित हो सकते हैं कि वे कभी-कभी ऐसे काम करेंगे जो उन्हें नहीं करने चाहिए: और वे ऐसे काम नहीं करेंगे जो उन्हें करने चाहिए। लेकिन अगर और जब हममें से किसी को भी इससे नुकसान होता है तो इसका उपाय क्या है? हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की हमारी प्रक्रिया कुशल है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की हमारी प्रक्रिया नहीं है। जिस तरह से कोयले को जीतने के लिए कुदाल और फावड़ा अब उपयुक्त नहीं है, उसी तरह से नए युग में स्वतंत्रता जीतने के लिए परमादेश, प्रमाण पत्र और कार्रवाई की प्रक्रिया भी उपयुक्त नहीं है। उन्हें नई और अद्यतन मशीनरी, घोषणाओं, निषेधाज्ञाओं और लापरवाही के लिए कार्रवाई द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए... यह संसद का काम नहीं है.... न्यायालयों को यह करना चाहिए। आगे आने वाले सभी महान कार्यों में से यह सबसे बड़ा है। कार्यपालिका की नई शक्तियों का उचित उपयोग कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाता है; लेकिन इसका दुरुपयोग एक अधिनायकवादी राज्य की ओर ले जाता है। इस देश में ऐसा कभी नहीं होने दिया जाना चाहिए।

47. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने पर राज्य के विरुद्ध मौद्रिक क्षतिपूर्ति के पुरस्कार द्वारा गलत को सुधारने का एक समान दृष्टिकोण आयरलैंड के न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है, जिसका लिखित संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन भारतीय संविधान की तरह इसमें भी उन अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, इसने आयरलैंड के न्यायालयों को न केवल उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, बल्कि

स्वयं राज्य के विरुद्ध भी, क्षतिपूर्ति के पुरस्कार सहित उपचार विकसित करने से नहीं रोका है।

48. द स्टेट (एट द प्रॉसिक््यूशन ऑफ किन) बनाम रयान (1965) आईआर 70 122 में ओ'डेलाघ सीजे की जानकारीपूर्ण और शिक्षाप्रद टिप्पणियाँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देने में संविधान का यह उद्देश्य नहीं था कि इन अधिकारों को नकार दिया जाए या उनसे छेड़छाड़ की जाए। इसका उद्देश्य यह था कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए जा रहे थे और न्यायालय उन अधिकारों के संरक्षक थे। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों को बिना किसी दंड के खरीद नहीं सकता या उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और इस संबंध में न्यायालय की शक्तियाँ उतनी ही व्यापक हैं जितनी संविधान की रक्षा की आवश्यकता है।

49. बायर्न बनाम आयरलैंड (1972) आईआर 241 में, वॉल्श, जे. ने पृष्ठ 264 पर राय दी:

संविधान के कई हिस्सों में नागरिकों के लाभ के लिए कुछ प्रावधान करने का कर्तव्य राज्य पर लगाया गया है, जो नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और जब तक संविधान में कोई विपरीत प्रावधान नहीं दिखाई देता है, तब तक संविधान को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय बनाने वाला माना जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि, जहां अधिकार राज्य द्वारा गारंटीकृत हैं, वहां राज्य के खिलाफ उपाय की मांग की जानी चाहिए, यदि लगाए गए संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता हुई है।

50. महाराज बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो (1978) 2 ऑल ईआर 670 में, प्रिवी काउंसिल ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के संविधान की धारा 6 की व्याख्या करते हुए माना कि हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन यह बुनियादी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के लिए 'निवारण' के रूप में मौद्रिक मुआवजे के आदेश की अनुमति देता है। बहुमत के लिए बोलते हुए लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा:

अटॉर्नी जनरल की ओर से तर्क दिया गया कि धारा 6(2) मौद्रिक मुआवजे के आदेश की अनुमति नहीं देती है, इस तथ्य के बावजूद कि जौंडौ बनाम गुवाना के अटॉर्नी जनरल में इस तरह के निवारण का आदेश दिया गया था। उप-धारा में 'उक्त पूर्वगामी धाराओं के किसी भी प्रावधान के प्रवर्तन को लागू करने, या लागू कराना सुनिश्चित करने' के संदर्भ पर भरोसा किया गया, क्योंकि यही वह उद्देश्य है जिसके लिए आदेश आदि बनाए जा सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि मुआवजे के भुगतान का आदेश उन अधिकारों को लागू करने के बराबर नहीं है जिनका उल्लंघन किया गया है। उनके माननीयों के विचार में, जब धारा 1 के तहत संरक्षित अधिकार का उल्लंघन किया गया हो, तो मुआवजे के भुगतान का आदेश स्पष्ट रूप से 'निवारण' का एक रूप है, जिसे कोई व्यक्ति धारा 6(1) के तहत दावा करने का हकदार है और यह निवारण का एकमात्र व्यावहारिक रूप हो सकता है, जैसा कि अब तक तत्काल मामले में है। ऐसा आदेश देने का अधिकार उच्च न्यायालय को धारा 6(2) के पैरा (ए) द्वारा प्रदान किया गया है, अर्थात् इस धारा की उपधारा (1) के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी आवेदन पर सुनवाई करने और उस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र। आदेश देने, रिट जारी करने और निर्देश देने की अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण शक्तियाँ इसके सहायक हैं।

51. इसके बाद लॉर्ड डिप्लॉक ने टिप्पणी की (पृष्ठ 680 पर):

अंत में, उनके माननीय न्यायाधीश धारा 16 के तहत वसूली योग्य मौद्रिक मुआवजे के उपाय के बारे में कुछ कहेंगे, जहां दावेदार के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा स्वतंत्रता से वंचित करना है। यह दावा झूठे कारावास के अपराध के लिए क्षतिपूर्ति के लिए निजी कानून में दावा नहीं है, जिसके तहत वसूली योग्य क्षतिपूर्ति व्यापक है और इसमें प्रतिष्ठा की हानि के लिए क्षतिपूर्ति शामिल होगी। यह केवल स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए मुआवजे के लिए सार्वजनिक कानून में दावा है।

52. सिम्पसन बनाम अटॉर्नी जनरल [बेगेंट का मामला] (1994) NZLR. 667 में न्यूजीलैंड में अपील न्यायालय ने विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के अधिकारियों के संदर्भ में इस मुद्दे को बहुत विस्तृत तरीके से निपटाया। इसने पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए गैरकानूनी तलाशी जैसे अपकृत्यों के लिए प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार किया, जो न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स एक्ट, 1990 का उल्लंघन करते हैं। बिल ऑफ राइट्स द्वारा गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रवर्तन से निपटने के दौरान, जिसके लिए कोई विशिष्ट उपाय प्रदान नहीं किया गया था। हार्डी बॉयज़, जे. ने टिप्पणी की:

न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स एक्ट, जब तक कि यह एक खाली बयान से अधिक कुछ न हो, क्राउन द्वारा एक प्रतिबद्धता है कि सरकार की तीनों शाखाओं में जो लोग इसके कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हैं, वे उन अधिकारों का पालन करेंगे, जिनकी पुष्टि बिल द्वारा की गई है। मैं इस प्रतिबद्धता में निहित मानता हूं कि यह वास्तव में इसके महत्व के लिए आवश्यक है, कि न्यायालयों को न केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बिल का पालन करना चाहिए, बल्कि जहां अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वहां उचित और प्रभावी उपाय प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे यह सोचने का कोई कारण नहीं दिखता कि यह लिखित संविधान की शर्तों पर निर्भर होना चाहिए। बुनियादी मानवाधिकारों का आनंद लेना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और उनकी सुरक्षा प्रत्येक सभ्य राज्य का दायित्व है। वे समाज की संरचना में निहित और आवश्यक हैं। वे उस कानूनी या संवैधानिक रूप पर निर्भर नहीं हैं जिसमें उन्हें घोषित किया जाता है। जिस तर्क ने प्रिवी काउंसिल और आयरलैंड और भारत के न्यायालयों को उन मामलों में निष्कर्ष पर पहुंचाया है जिनका मैंने उल्लेख किया है (और वे केवल एक नमूना हैं) मेरी राय में न्यूजीलैंड बिल ऑफ राइट्स एक्ट के लिए समान रूप से मान्य है यदि इसे जीवन और अर्थ देना है।

53. अपील न्यायालय ने आयरिश न्यायालयों और प्रिवी काउंसिल के निर्णयों पर भरोसा किया और नीलाबती बेहरा बनाम राज्य (सुप्रा) में निर्धारित कानून का हवाला दिया:

एक और मूल्यवान अधिकार भारत से आता है, जहाँ संविधान सर्वोच्च न्यायालय को इसके तहत गारंटीकृत अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है। नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) सीआरएल. एलजे 2899 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पीट-पीटकर मारे गए एक युवक की माँ को राज्य के विरुद्ध हर्जाना देने का आदेश दिया। न्यायालय ने माना कि प्रवर्तन की उसकी शक्ति ने "नए उपकरण बनाने" का कर्तव्य लगाया, जिसमें से मुआवजा एक उचित उपाय था, जहाँ यह निवारण का एकमात्र उपलब्ध तरीका था। यह अपकृत्य में एक उपाय नहीं था, बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व पर आधारित सार्वजनिक कानून में एक उपाय था, जिस पर संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। आनंद, जे. की पृष्ठ 2912 पर ये टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं।

पीड़ित को केवल सिविल कानून में उपलब्ध उपायों तक सीमित रखने का पुराना सिद्धांत नागरिकों के अपूरणीय अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में न्यायालयों की भूमिका को बहुत सीमित कर देता है। न्यायालयों का दायित्व नागरिकों की

सामाजिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करना है क्योंकि न्यायालय और कानून लोगों के लिए हैं और उनसे उनकी आकांक्षाओं पर प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक कानून का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक शक्ति को सभ्य बनाना है, बल्कि नागरिकों को यह आश्वासन देना भी है कि वे एक कानूनी प्रणाली के तहत रहते हैं जिसका उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को संरक्षित करना है।

54. सिम्पसन मामले (सुप्रा) में अपील न्यायालय के पांचों सदस्यों में से प्रत्येक ने अलग-अलग निर्णय दिया, लेकिन पीड़ित को बिल ऑफ राइट्स एक्ट के तहत गारंटीकृत उसके अधिकारों के उल्लंघन के लिए आर्थिक मुआवजा देने के संबंध में राय में एकमतता थी, भले ही बिल ऑफ राइट्स एक्ट में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो।

55. इस प्रकार, संक्षेप में, यह अब अधिकांश न्यायक्षेत्रों में एक अच्छी तरह से स्वीकृत प्रस्ताव है कि मौद्रिक या आर्थिक मुआवजा एक उचित और वास्तव में एक प्रभावी और कभी-कभी शायद लोक सेवकों द्वारा नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार के स्थापित उल्लंघन के निवारण के लिए एकमात्र उपयुक्त उपाय है और राज्य उनके कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। नागरिक का दावा सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है जिसके लिए संप्रभु प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं है और नागरिक को राज्य से मुआवजे की राशि प्राप्त करनी चाहिए, जिसे गलत करने वाले द्वारा क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा। मुआवजे के आकलन में, प्रतिपूरक तत्व पर जोर दिया जाना चाहिए न कि दंडात्मक तत्व पर। उद्देश्य घावों पर मरहम लगाना है और अपराधी या अपराधी को दंडित करना नहीं है, क्योंकि अपराध के लिए उचित दंड देना (मुआवजे पर ध्यान दिए बिना) आपराधिक न्यायालयों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसे करने के लिए राज्य, कानून में, कर्तव्यबद्ध है। सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार में मुआवजा देने का निर्णय किसी अन्य कार्यवाही जैसे कि नुकसान के लिए दीवानी मुकदमा, जो पीड़ित या मृतक पीड़ित के उत्तराधिकारियों को राज्य के पदाधिकारियों द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उसी मामले के संबंध में विधिपूर्वक उपलब्ध है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। मुआवजे की मात्रा, निश्चित रूप से, प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगी और उस संबंध में कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला विकसित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार के तहत नागरिक के मौलिक अधिकारों पर स्थापित आक्रमण के लिए गलत का निवारण करने के लिए राहत पारंपरिक उपचारों के अतिरिक्त है और उनका अपमान नहीं करती है। न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि और राज्य द्वारा किए गए गलत का निवारण करने के लिए भुगतान की गई राशि, किसी दिए गए मामले में, किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है जो किसी दीवानी मुकदमे में दावेदार को नुकसान के रूप में दी जा सकती है।

56. इस निर्णय को प्रस्तुत करने से पूर्व हम सामान्यतः राज्यों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं तथा विशेष रूप से न्यायालय के न्यायमित्र डॉ. ए.एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करना चाहते हैं।